

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु कार्यक्रमों को संचालित कर हितग्राहियों को क्रियान्वयन हेतु	450000	निम्नांकित घटक शहरी गरीबों के लिए क्रियान्वित होंगे :- 1. सामाजिक जुड़ाव एवं संस्थागत विकास 2. कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार 3. स्व-स्वरोजगार कार्यक्रम 4. प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास 5. शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता 6. शहरी वेधरों के लिए आश्रय की योजना 7. प्रशासनिक एवं अन्य व्यय 8. सूचना सम्प्रेषण मद	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूह गठन-3691, क्षेत्र स्तरीय संगठन निर्माण-178 2. स्व-सहायता समूहों को आवर्ती निधि-3058, क्षेत्र स्तरीय संगठन आवर्ती निधि-209 3. हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण-1305 4. हितग्राहियों का प्रमाणीकरण-2204 5. व्यक्तिगत ऋण-4129 6. समूह ऋण-345 7. बैंक लिंकेज ऋण-1916 8. राज्य/सिटी मिशन प्रबंधक-68, सामुदायिक संगठन-181 तथा सपोर्न स्टॉफ-50 9. सर्वोक्षित पथा विक्रेता-31895, परिचय पत्र वितरण-23170 10. संचालित आश्रय स्थल -03, निर्माणाधीन-19 एवं निर्माणपुर्ण आश्रय स्थल -05	450000	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्मार्ट सिटी	राजधानी रायपुर का स्मार्ट सिटी के मापदण्ड अनुरूप विकसित करना।	3960000	स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (रिट्रो फिटिंग), नगर नवीकरण (पुनर्विकास) और नगर विस्तार (हरित क्षेत्र विकास) के अतिरिक्त पैन सिटी प्रयास, जिसमें शहर के बड़े भागों को कवर करते हुए सुव्यवस्थित समाधान (स्मार्ट सॉल्यूशन) लागू किया जाता है	-		
3.	स्वच्छ भारत अभियान	यह केन्द्रीय योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य के कुल 426637 शौचालय विहित आवास गृहों में से 341310 आवास गृहों में निजी शौचालय 14780 कम्युनिटी शौचालय एवं 2000 सीटर पब्लिक शौचालय का निर्माण किया जाना है ।	100000	यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार निर्मांकित 05 घटक में योजना का क्रियान्वयन होगा:- 1. सार्वजनिक शौचालय 2. निजी/व्यक्तिगत शौचालय 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 4. सूचना शिक्षा एवं सम्प्रेषण 5. कैपेसिटी बिल्डिंग/प्रशासनिक व्यय	योजनांतर्गत सामुदायिक एवं निजी शौचालयों का निर्माण किया गया है:-	294950	सार्वजनिक शौचालय-कुल 83 ब्लॉक में 546 सीट निजी शौचालय- 2018-19 के लिए 188352

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सबके लिए आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना "सबके लिए आवास योजना" के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक के लिये क्रियान्वयन होंगे:- 1. झुग्गी बस्ती पुर्नविकास 2. ऋण से जुड़ी व्याज 3. सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी के किफायती आवास का निर्माण 4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवासों का निर्माण	5950000	वर्ष 2015-2022 तक सभी पात्र परिवारों को 30 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्रफल आकार के अधोसंरचनायुक्त पक्के आवास प्रदान करने के लिए केन्द्राय सहायता का प्रावधान है । प्रथम श्रेणी के शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए 04 चरणों में क्रियान्वयन किया जाना है ।	1. आईएसएसआर घटक अंतर्गत निर्मित आवास-निरंक 2. एएचपी घटक अंतर्गत पूर्ण आवास -353 एवं प्रगतिरत आवास-41123 3. बीएलसी घटक अंतर्गत पूर्ण आवास -8620 एवं प्रगतिरत आवास-27591 कुल पूर्ण आवास 8973 एवं प्रगतिरत 68714 का निर्माण योजनांतर्गत किया गया है ।	1059442	
5.	अमृत मिशन	अमृत मिशन हेतु प्रमुख अवरचना घटक निम्नानुसार है:- 1. जलापूर्ति 2. सिवरेज सुविधाएं ओर सेटेज प्रबंधन 3. बाढ़ को कम करने के लिए बर्षा जल नाले	2360000	राज्य के 09 शहरों-रायपुर, बिलसपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर को अमृत मिशन हेतु चयनित किया गया ।	योजनांतर्गत प्रदेश के 09 शहर (रायपुर, बिलसपुर, भिलाई, राजनांदगांव, कोरबा, जगदलपुर, अंबिकापुर, दुर्ग एवं रायगढ़) की जल प्रदाय योजनाओं का कार्य प्रगतिरत एवं 02 शहर (रायपुर एवं राजनांदगांव) में सीवेज मैनेजमेंट	4688620	

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां	भौतिक वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. पैदल मार्ग, गैर-मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल					
		5. बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्को और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना ।					
6.	झुग्गी झोपड़ी पेयजल तथा शौचालय निर्माण	गंदी बस्ती क्षेत्रों में पेयजल एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना	94100	नगरीय निकायों में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था	165	नगरीय निकाय	94100
7.	वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	नगरीय निकायों में स्वच्छ पेयजल प्रदाय किया जाना है ।	50000	168 निकाओं में आवश्यकतानुसार वॉटर ए.टी.एम. की स्थापना	12	नगरीय निकायों में 91 नग वाटर ए.टी.एम. की स्थापना	50000
8.	मूलभूत सुविधाओं हेतु अनुदान	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुसार नगरीय निकायों को कार्ययोजना अनुसार पेयजल, प्रकाश, सार्वजनिक शौचालय साफ सफाई एवं सामुदायिक भवन आदि के लिए अनुदान	770890	168 नगरीय निकायों के लिए निम्नांकित कार्य योजना है:- 1. सीसी रोड निर्माण 2. नाली निर्माण 3. डब्ल्यू बीएम रोड निर्माण 4. प्रकाश व्यवस्था 5. सामुदायिक भवन 6. ठोस अवशिष्ट सामग्री क्रय प्रबंधन	165	नगरीय निकाय	770890

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	विशिष्ट प्रयोजनार्थ	योजनांतर्गत नगरीय निकायों को अन्य विकास कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान निश्चित अनुपात में स्वीकृत किया जाता है ।	150000	नगरीय निकायों द्वारा तैयार विकास की योजनाओं हेतु तैयार प्रस्तावों पर वित्त विभाग की सहमति अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना में नगर निगम हेतु 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत अनुदान तथा नगर पालिका पंचायत हेतु 60 प्रतिशत ऋण एवं 40 प्रतिशत अनुदान का अनुपात निर्धारित है	-		
10.	स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना	1350	जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएंगे। 1500 लाभान्वित होंगे ।	-		
11.	नगरीय निकायों की अधोसंरचना विकास योजना	नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास की योजनाओं हेतु अनुदान एवं ऋण	3710796	अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान राशि की मांग की गई है जिसमें अंतर्गत निम्नान्वित कार्य प्रमुखतः से किया जाना है । 1. मास्टर प्लान/सी.डी.पी के मुख्य मार्ग 2. फ्लार्ड ओव्हर निर्माण 3. मल्टी लेवर पार्किंग स्थल निर्माण	165	नगरीय निकाय	3740796

निष्पादन बजट वर्ष 2019-20

विभाग- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
विभागाध्यक्ष- संचालक,नगर प्रशासन,छत्तीसगढ़

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट अनुमान 2019-20	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	राशि हजार ₹ में		टिप्पणियां
					वास्तविक उपलब्धियां		
					भौतिक	वित्तीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
				4. पशु वंध गृह निर्माण 5. नगरीय जल प्रदाय योजना 6. स्पोर्ट्स काम्पलेक्स			